Supplement—II Regd. No. CHD/0093/2015-2017

Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 46-2015] CHANDIGARH, TUESDAY, NOVEMBER 17, 2015 (KARTIKA 26, 1937 SAKA)

General Review

उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा की वर्ष 2014–2015 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा

दिनांक 29 अक्तूबर, 2015

क्रमांक 1/1-2015 आंकड़ा.–प्रथम नवम्बर, 1966 को हरियाणा राज्य के अस्तित्व में आने के पश्चात् शिक्षा का गुणात्मक तथा परिमाणात्मक रूप में कई गुणा विस्तार हुआ है। विस्तार का यह ग्राफ वर्ष 2014–15 में भी बढ़ता रहा। राज्य में शिक्षा की संस्थात्मक क्षमता की वृद्धि हुई, जिससे शिक्षा का विस्तार विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ। राज्य उच्च तकनीक अपना कर उत्कृष्ट तकनीकी का पूरा लाभ उठा रहा है ।

वर्ष 2014–2015 में उच्चतर शिक्षा पर कुल 119053.31/–लाख रुपये की राशि व्यय की गई, इसमें योजनेत्तर पक्ष पर 73780.54/– लाख रुपये, योजना पक्ष पर 45240.66/– लाख रुपये तथा केन्द्रीय संचालित कार्यक्रमों पर 32.11/– लाख रुपये व्यय हुए। राज्य में सात विश्वविद्यालय महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र, चौ0 देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा, भक्त फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलां, सोनीपत, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, मीरपुर, रेवाड़ी, चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जीन्द, चौधरी बंसी लाल विश्वविद्यालय, भिवानी और एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय जॉटपाली, महेन्द्रगढ़ उच्च शिक्षा प्रदान कर रहे हैं।

वर्ष 2014–2015 में 202 महाविद्यालयों, 1 केन्द्रीय विश्वविद्यालय एवं 7 विश्वविद्यालयों में लगभग 461486 छात्रों को शिक्षा प्रदान की जा रही है तथा इनमें 6104 प्रोफैसर/सह– प्राध्यापकों/सहायक प्राध्यापकों ने शिक्षा प्रदान की।

अनुसूचित जातियों तथा समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं। मेधावी तथा मैरिट में आने वाले विद्यार्थियों के लिए भी विभिन्न योजनायें हरियाणा सरकार द्वारा राज्य भर में चलाई जा रही हैं ताकि ये विद्यार्थी अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। वर्ष 2014–15 में विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत 1,06,18,66,511/– रु0 की राशि खर्च हुई तथा इससे कुल 98917 छात्र/छात्रायें लाभान्वित हुए।

वर्ष 2014–15 की रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान ''कमायें जब आप शिक्षा पायें'' योजना के अन्तर्गत सभी राजकीय महाविद्यालयों को 100.00 लाख रुपये की राशि वितरित की गई एवं इस योजना के तहत लगभग 5000 विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

मानव संसाधन विकास योजना के अन्तर्गत विभाग द्वारा विभिन्न महाविद्यालयों में सेमिनार, रिफ्रेशर कोर्स कार्यशालाएं तथा अनुस्थापन पाठ्यक्रम आयोजित किए गए। राज्य के राजकीय महाविद्यालयों में रोजगार कक्षों हेतु 50.00 लाख रु0 की राशि व्यय की गई।

राज्य में विद्यार्थी कैडेट्स/स्वयं सेवकों के चहुंमुखी विकास लाने के उद्देश्य से एन0सी0सी0/एन0एस0एस0 कार्यक्रम चलाए गए हैं। इन एन0सी0सी0 कैडेट्स को प्रशिक्षण देने के लिए एवं उनके अन्य खर्चों 15,03,80,000/– लाख रु0 की राशि खर्च की गई। एन0एस0एस0 सेवकों की पंजीकृत संख्या 1,26,120 थी तथा एन0एस0एस0 कार्यक्रमों के लिए कुल 4,99,23,000/– रु0 की राशि प्रदान की गई।

वर्ष 2014–15 में आम जनता के ज्ञान वर्धन हेतु एवं पढ़ने की आदत डालने के लिए एक केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय, 19 जिला पुस्तकालय तथा 7 उपमण्डल पुस्तकालय राज्य में कार्य कर रहे थे । इस अवधि के दौरान 105 राजकीय महाविद्यालयों को 200.00 लाख रु0 की राशि एवं 8 जिला पुस्तकालयों (पंचकुला, यमुनानगर, कैथल, पानीपत, रेवाड़ी, नूंह, झज्जर तथा फतेहाबाद) के स्टाफ की सैलरी हेतु 150.00 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई।

वर्ष 2014–2015 के दौरान श्रीमती गीता भुक्कल एवं श्री राम बिलास शर्मा शिक्षा मंत्री के योग्य निर्देशन में निदेशालय ने शिक्षा को एक नई गति प्रदान की। श्री एस0एस0 प्रसाद आई0ए0एस0 एवं श्री विजय वर्धन आई0ए0एस0, अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, उच्चतर शिक्षा के पद पर रहे। श्री अंकुर गुप्ता आई0ए0एस0 एवं श्री बलराज सिंह आई0ए0एस0 ने महानिदेशक उच्चतर शिक्षा, हरियाणा के पद पर कार्य किया।

विजय वर्धन,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
उच्चतर शिक्षा विभाग।

चण्डीगढ़ :
दिनांक : 14.9.2015.

Review of the Annual Administrative Report of the Higher Education Department, Haryana for the year 2014-15

The 29th October, 2015

No. 1/1-2015 Stats.—The Haryana State has witnessed many fold increase in the field of Higher Education quantitatively as well as qualitatively since 1st November, 1966. The graph of expansion of Higher Education kept moving upward during 2014-15 also. The institutional capacity of the State has increased, which has facilitated expansion of education especially in rural areas. The State Higher Education has become hi-tech and is reaping the benefits of advanced technology.

During 2014-15, a total amount of Rs. 119053.31/- lakh was spent on Higher Education, Rs. 73780.54/- lakh on non-plan side, Rs. 45240.66/- lakh on plan side and 32.11/- lakh was spent on centrally sponsored schemes. Seven State Universities namely M.D.U. Rohtak, K.U. Kurukshetra, C.D.L.U, Sirsa, B.P.S. M.V. Khanpur Kalan, Sonepat, Indira Gandhi University, Meerpur, Rewari, Chaudhry Ranbir Singh University, Jind, Chaudhry Bansi Lal University, Bhiwani and One Central University, Jantpali, Mahendergarh have been providing higher education in the State.

During 2014-15, 202 Colleges, 1 Central University and 7 State Universities imparted education to 4,61,486 students and these were served by 6104 Professors/ Associate Professors/ Asstt. Professor.

Stipends were provided to students belonging to S.C. category and weaker sections of the society. Various schemes are also being run to provide financial help to meritorious students and brilliant students so that these students can complete their eduction. During the year 2014-2015 an amount of Rs. 1,06,18,66,511/- was spent amongst 98917 students under various scholarship schemes.

During reporting period *i.e.* 2014-15 a grant of Rs. 100.00 lakh was utilized for the scheme 'Earn while you learn' which was distributed to all Government Colleges and 5000 students were benefited under this scheme.

Under Human Resource Development Scheme, seminars, refresher courses and orientation courses were sponsored by the department in different colleges. An amount of Rs. 50.00 lakh was spent on placement cells in Government Colleges of the State.

N.C.C. and N.S.S. programmes are being run in the State with the aim of bringing all round development of student cadets/volunteers. An amount of Rs. 15,03,80,000/- lakh was spent on training and other expenses of N.C.C.

cadets. The enrolled strength of N.S.S. volunteers was 1,26,120 and a total budget of Rs. 4,99,23,000/- was provided for conducting N.S.S. programmes.

For disseminating knowledge and inculcating the reading habit in general public, 01 Central State Library, 19 District Libraries, 7 Sub Divisional Libraries were functioning in the State during 2014-15. During this period Rs. 200.00 lakh was allocated for 105 Government Colleges and Rs.150.00 lakh was allotted for 8 District Libraries (Panchkula, Yamunanagar, Kaithal, Panipat, Rewari, Nuh, Jhajjar and Fatehabad) for augmentation.

Smt. Geeta Bhukkal and Sh. Ram Bilas Sharma were the Education Ministers during 2014-15. Sh. S.S. Prasad, IAS and Sh. Vijay Vardhan, IAS held the office of Additional Chief Secretary to Government of Haryana, Higher Education Department. During the reporting period Sh. Ankur Gupta, IAS and Sh. Balraj Singh IAS, held the office of Director General Higher Education, Haryana.

VIJAI VARDHAN,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Higher Education Department.

Chandigarh :
The 14th September, 2015.

माध्यमिक शिक्षा विभाग, हरियाणा की वर्ष 2014–15 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा

दिनांक 2 नवम्बर, 2015

क्रमांक 1/13-2015 आंकड़ा.(2)–01 नवम्बर, 1966 को हरियाणा राज्य के अस्तित्व में आने के पश्चात् शिक्षा का तेजी से गुणात्मक एवं परिमाणात्मक विस्तार हुआ है। राज्य ने शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार में विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण तथा विभिन्न स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान विभाग की गतिविधियों की प्राथमिकता वाले क्षेत्र थे। विद्यार्थियों के सीखने का स्तर अपेक्षित स्तर का नहीं था जिसके लिए सतत् प्रयास मास अक्तूबर, 2014 से किए जा रहे हैं। अतः बड़े पैमाने पर विद्यालयों का निरीक्षण किया जा रहा है जिसका दीर्घावधि में परिणाम निकलेगा।

2. वर्ष 2014–15 में माध्यमिक शिक्षा पर कुल ₹ 2569.99 करोड़ खर्च किए गए। रिपोर्टाधीन अवधि में राज्य में शिक्षा प्रदान करने के लिए 3361 उच्च विद्यालय, 4210 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अस्तित्व में थे। कुल 50,180 अध्यापक राज्य में विभिन्न प्रकार के राजकीय विद्यालयों में पढ़ा रहे थे। राज्य में उच्च स्तर पर 8.64 लाख तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर 6.33 लाख विद्यार्थी दाखिल किए गए।

3. अनुसूचित जातियों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के बच्चों, विशेषकर छात्राओं को निःशुल्क वर्दी, लेखन–सामग्री, पाठ्य–पुस्तकें, वृतिका तथा छात्रवृत्तियों जैसे प्रोत्साहन दिए गए। बालिका शिक्षा पर बल देने के लिए उनको विशेष प्रोत्साहन दिए गए। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान राज्य में पढ़ने वाले समाज के आरक्षित एवं अन्य कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों के लिए प्रोत्साहन/वित्तीय सहायता हेतु ₹ 179.70 करोड़ खर्च किए गए।

4. राज्य सरकार ने राज्य में बालिकाओं की शिक्षा में सुधार लाने तथा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को सफल बनाने के लिए साक्षरता परियोजनाओं को गति दी है।

5. दिनांक 01.04.2014 से 25.10.2014 की अवधि के दौरान श्रीमती गीता भुक्कल, शिक्षा मन्त्री रहीं तथा श्री राव दान सिंह, मुख्य संसदीय सचिव उनके साथ सम्बद्ध थे। इसके उपरान्त 26.10.2014 से 31.03.2015 तक श्री रामबिलास शर्मा, शिक्षा मन्त्री रहे।

6. श्रीमती सुरीना राजन, आई0ए0एस0, अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, शिक्षा विभाग में 01.04.2014 से 12.11.2014 तक कार्यरत रहीं। इसके उपरान्त श्री टी0 सी0 गुप्ता, आई0ए0एस0 प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, विद्यालय शिक्षा विभाग में 31.03.2015 तक कार्यरत रहे।

7. निम्नोक्त द्वारा निदेशक माध्यमिक शिक्षा के पद पर कार्य किया गया :–

(i) 01.04.2014 से 02.05.2014 की अवधि के दौरान श्री चन्द्र शेखर, आई0ए0एस0।

(ii) 05.05.2014 से 24.11.2014 की अवधि के दौरान श्री विवेक अत्रेय, आई0ए0एस0।

(iii) 25.11.2014 से 31.03.2015 की अवधि के दौरान श्री एम.एल.कौशिक, आई0ए0एस0।

टी0 सी0 गुप्ता,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
विद्यालय शिक्षा विभाग।

दिनांक : 10.08.2015.

Review of the Annual Administrative Report of the Secondary Education Department, Haryana for the Year 2014-15

The 2nd November, 2015

No. 1/13-2015 Stats.(2).—Ever since the inception of State of Haryana on 1st November 1966, there has been rapid expansion in the field of education, both in terms of quality and quantity. The State has made a remarkable progress in the extension of educational facilities, especially in rural areas. Universalization of education and qualitative improvement in education at different levels were the priority areas of the Department during the period under report. However, the learning level outcome of students was not witnessed upto the desired level for which strenuous efforts were made after October, 2014. Rigorous inspection of schools has been undertaken at all the levels which will yield results in long run.

2. During 2014-2015, a total amount of ₹ 2569.99 crore was provided for Secondary Education. 3361 High Schools & 4210 Senior Secondary Schools were functioning in the State during the year under report, for dissemination of education. A total of 50,180 teachers were teaching in various Government schools and 8.64 lac students at High level, 6.33 lac students at Senior Secondary level were enrolled in the State.

3. Various incentives like free uniform, stationery, text books, stipends and scholarships were provided to the students belonging to the Scheduled Castes and Weaker Sections of the society. Special emphasis was laid on providing greater incentives to girl students. During the period under report, an amount of ₹ 179.70 crore was spent on these incentives / financial aid to students of reserved categories and other weaker sections of society studying in the State.

4. The Department has also geared up Literacy projects to improve girl education and to make the National Literacy Mission a success in the State.

5. During the period from 01.04.2014 to 25.10.2014, Smt. Geeta Bhukkal was the Education Minister and Sh. Rao Dan Singh, Chief Parliamentary Secretary was attached to the Education Minister and thereafter, Sh. Ram Bilas Sharma was the Education Minister from 26.10.2014 to 31.03.2015.

6. Smt. Surina Rajan, IAS held the office of Additional Chief Secretary, Government of Haryana, School Education from 01.04.2014 to 12.11.2014. Thereafter Sh. T.C. Gupta, IAS, remained on the post of Principal Secretary, School Education Department upto 31.03.2015.

7. The Post of Director, Secondary Education was held by the following :-

(i) Sh. Chander Shakhar, IAS from 01.04.2014 to 02.05.2014.

(ii) Sh. Vivek Attray, IAS from 05.05.2014 to 24.11.2014.

(iii) Sh. M.L. Kaushik, IAS, from 25.11.2014 to 31.03.2015.

T. C. GUPTA,
Principal Secretary to Government of Haryana,
School Education Department, Chandigarh.

The 10th August, 2015.

सिंचाई विभाग, हरियाणा की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट वर्ष 2013–2014 की समीक्षा

दिनांक 16 अक्तूबर, 2015

क्रमांक 312-13/362/26/Sts/2013-14.—हरियाणा भारत देश का एक छोटा राज्य है जो कि 1 नवम्बर, 1966 को पंजाब के विभाजन पर बना था। यह देश के उत्तर पश्चिम में स्थित है और इसका भौगोलिक क्षेत्र 4.4 मिलियन हैक्टेयर और कृषि योग्य क्षेत्रफल 3.9. मिलियन हैक्टेयर है। राज्य का उत्तरी हिस्सा शिवालिक की पहाड़ियों से घिरा हुआ है और पूर्व में यमुना नदी है। दक्षिण में दिल्ली व अरावली की पर्वत माला है और दक्षिण पश्चिम में राजस्थान का मरुस्थल है। उत्तर पश्चिम में पंजाब की सीमा के साथ–साथ घग्गर नदी है। राज्य इन्डस बेसिन व गंगा के मध्य (घग्गर व यमुना नदी के मध्य) में है व इसकी स्थिति उत्तरी मैदानी क्षेत्र में लम्बाई में 74 डिग्री से 78 डिग्री पूर्व व कोणात्मक दृष्टि में 27 डिग्री से 31 डिग्री उत्तर में है।

वर्तमान में उपलब्ध पानी की 85 प्रतिशत मात्रा का उपयोग कृषि क्षेत्र में किया जाता है। राज्य में अधिकांश खाद्य सामग्री की फसलों को उगाया जाता है और उगाये गये अनाज की मात्रा भारतीय राष्ट्रीय औसत की अपेक्षा 30–40 प्रतिशत अधिक है सरकार सिंचाई व जल निकासी के कार्यों को अत्यधिक प्राथमिकता प्रदान करती है और इस क्षेत्र में योजना खर्च व वास्तविक बजट का लगभग 25 प्रतिशत खर्च के लिए प्रदान करती है। तदनुसार राज्य के कृषि योग्य क्षेत्र के 75 प्रतिशत क्षेत्र को नहरों द्वारा सिंचित किया जाता है। सिंचाई क्षमता मात्र 70 प्रतिशत है जो कि सिंचाई प्रणाली के लिए पानी की सीमित उपलब्धता को दर्शाता है।

राज्य में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने के लिए बड़ी व मध्यम सिंचाई परियोजनाओं (मेजर एण्ड मिडियम इरिगेशन प्रोजैक्टस) को प्राथमिकता दी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2013–14 के दौरान 22.19 लाख हैक्टेयर के क्षेत्र को नहरों द्वारा सिंचित किया गया।

नहरी व जल निकास नेटवर्क के चलाने व उसके रख–रखाव के लिए हरियाणा सिंचाई विभाग जिम्मेवार है। इसके अतिरिक्त विभिन्न जल संसाधन परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार करना है और जल मार्गों को पक्का करने व कमान क्षेत्र में विकास के अन्य कार्यों को करने के लिए कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण (काडा) इस विभाग का सहभागी है। इस विभाग को हरियाणा सिंचाई अनुसंधान प्रबन्धन संस्थान (हिरमी) प्रशिक्षण व अनुसंधान केन्द्र के रूप में सहभागी है।

सिंचाई विभाग द्वारा प्रदान की गई सुविधाएं व उद्देश्य

सिंचाई विभाग, हरियाणा के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:–

1. सामान्य प्रशासन विभाग को आबंटित मामलों को छोड़कर, सिंचाई विभाग के वर्ग-I और वर्ग-II से संबंधित अधिकारियों और विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कर्मचारियों के स्थापना मामले ।
2. बाढ़ सुरक्षा, जल निकासी और जल भराव रोकने हेतु कार्य–इनका निर्माण और रखरखाव ।
3. पंचवर्षीय योजनाओं और भविष्य की योजनाओं की सिंचाई परियोजनाएं- इनकी शोध और अन्वेषण कार्य ।
4. सिंचाई राजस्व - कर उगाही से संबन्धित सभी मामले ।
5. राज्य में सिंचाई योजनाएँ और परियोजनाएं, बहुउद्देशीय नदी योजनाएँ, बढ़ी और मध्यम सिंचाई योजनाएँ और लघु सिंचाई योजनाएँ ।
6. कार्यरत राज्य नहर प्रणाली- इनके रखरखाव व संचालन संबंधी कार्य ।
7. अन्तर्देशीय जहाज अधिनियम, 1917 (1917 का अधिनियम 1) से उत्पन्न मामलों को छोड़कर शिपिंग और नेवीगेशन नहरों के कार्य ।
8. राज्य के स्वामित्व वाले सिंचाई नलकूपों से संबन्धित मामले ।
9. भारतीय सर्वेक्षण कार्य समन्वय के सिंचाई विभाग से संबन्धित कार्य ।
10. सतलुज-यमुना लिंक नहर, अपर यमुना बोर्ड, अन्तर्राज्यीय जल विवाद, दिल्ली जल आपूर्ति से संबन्धित अन्तर्राज्यीय मामले आदि-इत्यादि ।
11. हरियाणा राज्य लघु सिंचाई और नलकूप निगम से संबन्धित सभी मामले ।
12. हरियाणा सिंचाई अनुसंधान और प्रबंधन संस्थान से संबन्धित सभी कार्य ।
13. कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण से संबन्धित सभी मामले ।
14. सिंचाई परियोजनाओं के प्रयोजन के लिए भूमि अधिग्रहण और भूमि मुआवजे के भुगतान मामले ।

वर्ष 2013–2014 की उपलब्धियां

वर्ष 2013–14 की मुख्य उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:–

1. वर्ष 2012–13 के दौरान सिंचित 22.04 लाख हैक्टेयर के क्षेत्र की तुलना में वर्ष 2013–14 में 22.19 लाख हैक्टेयर के क्षेत्र को सिंचित किया गया।
2. इस वर्ष नहरों के 17.91 मिलियन वर्गफुट क्षेत्र को पक्का किया गया।
3. कृषि, औद्योगिक, पीने के पानी व अन्य उद्देश्यों के लिए दिये गये पानी से 5793.35 लाख रुपये का राजस्व एकत्रित किया गया।

राम निवास,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग, चण्डीगढ़।

Review of Annual Administrative Report of Haryana Irrigation Department for the Year 2013-14

The 16th October, 2015

No. 312-13/362/26/Sts/2013-14 .—Haryana a State of the Union of India, was carved out of the composite State of Punjab on November 1st, 1966. It is situated in the North West of the country and covers a geographical area of 4.4 million hectares and cultural area of 3.9 million hectares. The State in North is bounded/by Shivalik range of mountains and in the East by River Yamuna. Aravali range running South of Delhi and desert of Rajasthan for the boundary on the South West side. In North West, the River Ghaggar forms part of the boundary with Punjab State lies between the basins of Indus and Ganges (between River Ghaggar and Yamuna) and is located in the Northern plain between longitude 74 degree to 78 degree East and Latitude 27 degree to 31 degree North.

Agriculture is the major user sector of water utilizing about 85% of the present supplies. Yields of most of the major crops are high and average food grain yields are 30-40% higher than the Indian national average. This Government places top most priority to Irrigation and drainage and about 25% of its planned outleys and actual budget are dedicated to these sectors. Consequently, about 75% of the State's arable Lands are served by Irrigation Canals. However, the Irrigation intensity is only around 70% reflecting to the limited availability of water supplies for the system.

In the State priority has been given to major and medium Irrigation project to increase the irrigation facilities. As a result of which 22.19 lac Hectares of land was irrigated during the year 2013-14.

Haryana Irrigation Department is primarily responsible for operation & maintenance of Canal & Drainage network, besides looking after planning design & construction of various water Resource Projects and is supported by Command Area Development Authority (CADA) for the construction of lined water courses and other command area Development activities etc. It is also supported by Haryana Irrigation Research Management Institute (HIRMI) which caters as a Training and Research Centre.

OBJECTIVES & FACILITIES PROVIDED BY HARYANA IRRIGATION DEPARTMENT

The broad objectives of Haryana Irrigation are as under:-

1. Establishment matters relating to Class-I and II Officers of Irrigation Department and the staff under the administrative control of the Department, except matters allotted to the General Administration Department.
2. Flood Protection, Drainage and Anti Water logging works— construction and maintenance thereof.
3. Irrigation Schemes for Five Year Plans and future Plans— investigation and formulation of.
4. Irrigation Revenue—All matters relating to including betterment levy.
5. Irrigation Schemes and Projects in the State, including Multipurpose River Schemes, Major, Medium and Minor Irrigation Schemes.
6. Running Canal System in the State Maintenance and Operation thereof.
7. Shipping and Navigation of canals excluding matters arising out of the Inland Vessels Act, 1917 (Act 1 of 1917).
8. State owned irrigation tubewells in the State— All matters relating to.
9. Survey of India Co-ordination of work relating to.
10. Inter-State matters related to SYL Canal, Upper Yamuna Board, Inter-State Water Disputes, Delhi Water Supply etc. etc.
11. Haryana State Minor Irrigation and Tubewell Corporation Ltd.— All matters relating to.
12. Haryana Irrigation Research and Management Institute—All matters relating to.
13. Command Area Development Authority—All matters relating to.
14. Land acquisition and payment of land compensation for the purpose of Irrigation projects.

ACHIEVEMENT OF THE YEAR 2013-14

The major achievements during the year 2013-14 are as under:-

1. 22.19 lacs Hectares of land has been irrigated during the year as compared to 22.04 lac hectares during 2012-13.
2. 17.91 M.Sq. ft. area of canal has been lined.
3. Total revenue received during the year was Rs. 5793.35 lacs on account of sale of water for Agricultural, Industrial, Drinking and other purpose.

RAM NIWAS,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Irrigation & Water Resources Department, Chandigarh.

53800—C.S.—H.G.P., Chd.